हिन्दी दैनिक
इंडिया वार्ता
R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104
सच के साथ-जन के साथ
लोकतंत्र में जनसरोकार का सशक्त माध्यम
वर्ष : 14 अंक : 303 | देहरादून,शुक्रवार 04 जुलाई 2025 | शुल्क : पचास पैसे | पृष्ठ संख्या : 08

आत्मिक वाणी

मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना अपने मन मे मेरी बातों को याद रखना क्योकि ऐसा करने से तेरे जीवन के दिन और तेरे वर्ष और बढ़ेगे। तेरा अधिकाधिक कल्याण ही होगा मेरे पुत्र करूणा और सच्चाई कभी तुझ से अलग ना हो तू उनको अपने गले का हार बना कर रखना और उनको अपने हृदय पटल पर लिख लेना तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में कृपा का पात्र होगा।

दिव्यांग मतदाताओं के बूथों को चिन्हित कर जरूरी .. 8

मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों के साथ की कांवड़ मेला-2025 की तैयारियों की समीक्षा

उत्तराखंड कांवड़ यात्रा सेवा एप बनाए जाने के दिए निर्देश

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिये उत्तराखंड कांवड़ सेवा एप बनाए जाने के निर्देश दिए है इसमें कांवड़ियों की सभी डिटेल उपलब्ध कराई जाए। इस एप का उपयोग हर वर्ष आयोजित होने वाले कांवड़ यात्रा के दौरान किया जा सकेगा, इस से कांवड़ यात्रा पहले से अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगी।

गुरूवार को मेला नियन्त्रण भवन हरिद्वार में उच्चाधिकारीयों के साथ कांवड मेला-2025 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के सकुशल एवं सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस एवं अन्य सम्बन्धित विभागों को चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा ऐसे राज्य जहां से अधिकांश कावड़िए आते हैं। उन राज्यों से परस्पर समन्वय, रियल टाइम डाटा शेयरिंग और सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी आवश्यक इनपुट्स साझा किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को आगामी कुंभ मेले का ट्रायल बताते हुए कहा कि ये अनुभव आगामी कुंभ मेले भी काम आएंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कावड़ यात्रा मार्गो पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न हो। उन्होंने कावड़ यात्रा से पहले सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों और होटलों में सुरक्षा ,मानकों का अनुपालन कराने के साथ ही फूड लाइसेंस और रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से चस्पा किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा मार्ग पर स्थित होटलों के नाम व होटल स्वामियों के नाम भी अनिवार्य रूप से लिखे हो एवं ओवर रेटिंग

- शेष पृष्ठ 7 पर ...

बीआईएस प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से भेंटकर उत्तराखंड में मानकीकरण से जुड़ी प्रमुख पहलुओं पर की चर्चा

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) देहरादून शाखा के निदेशक एवं प्रमुख श्री सौरभ तिवारी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल में शिक्षा क्षेत्र, उद्योग जगत एवं उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। मुख्यमंत्री श्री धामी से भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में मानकीकरण से संबंधित विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में भारतीय मानकों का अनिवार्य समावेश सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भवन निर्माण में आधारित विनियमों को अपनाने तथा विभिन्न सरकारी विभागों में प्रबंधन प्रणाली मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री धामी ने प्रतिनिधित्व मंडल को उत्तराखंड में मानकीकरण को सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण सेवाओं एवं विकास के लिए मानकीकरण अत्यंत आवश्यक है तथा यह पहल 'विकसित उत्तराखंड' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। बैठक में अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी, भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी मौजूद रहे।

दुष्कर्म के मुकदमें में फरार चल रहा ईनामी बदमाश गिरफ्तार

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो। बलात्कार के मुकदमें में पिछले वर्ष से फरार चल रहे 15 हजार रूपये के ईनामी अपराधी को एसटीएफ व प्रेमनगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सहरसा बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस गिरफ्त में आने से बचने के लिए चारो ओर पानी से घिरे टापू में छिपकर रह रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ, नवनीत सिंह भुल्लर द्वारा बताया गया कि एसटीएफ की कुमायूँ युनिट द्वारा कल थाना प्रेमनगर पुलिस के मुकदमे में फरार चल रहे 15 हजार के ईनामी अपराधी नितीश चैधरी पुत्र गोसांई चैधरी निवासी विल्स सिरवर थाना महिषी जिला सहरसा बिहार, को बिहार के सहरसा जिले के कनरिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। बताया कि मामले में एसटीएफ की टीम द्वारा प्राप्त तकनीकी तथा भौतिक सूचनाओं का विश्लेषण करते हुये पिछले 1 माह से काम किया जा रहा था। जिस पर अथक प्रयास करते हुए उक्त अपराधी की गिरफ्तारी की गयी। बताया कि चूँकि बिहार में इस समय बाढ़ का काफी प्रकोप रहता है हमारी टीम द्वारा स्थानीय बिहारी वेशभूषा में पैदल चल कर व नाव से कई नदियों को पार कर रेप के इस शातिर अपराधी की गिरफ्तारी की गयी है।

स्वच्छता अभियान में शामिल हुए सीएम धामी

हरिद्वार ,इंडिया वार्ता ब्यूरो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सीसीआर पहुँचकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रूद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वॉर्मिंग तथा पर्यावण असंतुलन को रोकने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने बताया कि वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस अभियान का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि माँ और प्रकृति दोनों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। यह अभियान समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भी संदेश देता।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीसीआर के पास गंगा घाट पहुँचकर सफाई एवं स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करते हुए स्वंय झाड़ू लगाकर स्वच्छता का सन्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि कचरे को एक नियत स्थान पर ही एकत्रित करें। अपने गांव- शहर को स्वच्छ

बनाने में सभी लोग अपनी-अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा बीमारियों के फैलने की संभावना भी नहीं रहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया मां गंगा आचमन लिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा का आचमन लिया तथा हाथ जोड़कर नमन करते हुए देश व प्रदेश की सु:ख, शान्ति एवं समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं से मिलकर ली व्यवस्थाओं की जानकारी विभिन्न राज्यों से आये श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अचानक अपने बीच पाकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाये तथा जमकर सेल्फी लीं। श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शालीनता, विनम्रता व सादगी की तारीफ की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी राज्यों से पहुँचे श्रद्धालुओं से सीधे संवाद करते हुए यातायात, रूकने, खान-पान सहित विभिन्न व्यवस्थाओं तथा सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिस पर सभी

- शेष पृष्ठ 7 पर ...

सम्पादकीय

डिजिटल साक्षरता और आनलाइन सुरक्षा

डिजिटल साक्षरता और आनलाइन सुरक्षा की कमी के कारण बच्चों के साथ आनलाइन अपराध, उत्पीड़न एवं शोषण की सम्भावना कई गुना अधिक होती है। बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो प्रकाश में आ पाते हैं। आमतौर पर वक्ताओं ने माना कि इन अपराधों से निपटने के लिए तमाम प्रतिभागियों जैसे कि सरकारी संस्थाओं, प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मीडिया, समाजसेवी संस्थाओं, स्कूलों, अध्यापकों तथा माता-पिता को मिलकर काम करने की जरूरत है। सबसे अधिक जरूरत तो बच्चों को इन अपराधों के खिलाफ जागरूक करने की है। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में अश्लील संदेश, अश्लील फोटो, पोर्न, साइबर बुलिंग, ब्लैकमेलिंग, बच्चों को डराना-धमकाना आदि शामिल हैं। बहुत बार तो बच्चों को डरा-धमकाकर उनसे बड़ी रकम भी ऐंठ ली जाती है। ऐसी बातें कई बार अखबारों और चैनल्स की खबर भी बनी हैं। आजकल दुनियाभर में बच्चों की आनलाइन सुरक्षा को काफी महत्व दिया जा रहा है लेकिन भारत अभी इस दिशा में काफी पीछे है। सच तो यह है कि कोई भी एक संस्था इस तरह के अपराधों से नहीं निपट सकती। इसके लिए सबको मिल-जुलकर काम करने की जरूरत है। बच्चों को जागरूक करने के लिए पुस्तकालयों की मदद ली जा सकती है। वहां ऐसे प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं जहां बच्चों को बड़ी संख्या में आनलाइन अपराधों के प्रति सचेत किया जा सके। आमतौर पर देखा गया है कि माता-पिता समझते हैं कि बच्चा जो कुछ कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी अध्यापकों और स्कूल की है। और अध्यापकों को लगता है कि बच्चों की प्राथमिक जिम्मेदारी माता-पिता की ही है। कहा जाता है कि घर वालों को यह देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन आजकल के समय में जहां बड़े शहरों के माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं, वे पूरे समय इस बात की निगरानी कैसे कर सकते हैं कि उनका बच्चा पूरे दिन कम्प्यूटर पर क्या कर रहा है। जबकि भारत में फेसबुक का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाले बच्चे ही हैं। कई बार विरोधाभासी बातें भी सामने आती हैं। जैसे कि बच्चों के लिए काम करने वाले संगठन कहते हैं कि बच्चों की जासूसी नहीं की जानी चाहिए। उन्हें आजादी देनी चाहिए। आनलाइन सुरक्षा की बात करने वाले कहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर अध्यापकों और परिवार वालों को नजर रखनी चाहिए।

हिन्दू राष्ट्र का ढोल और जातिवाद का आतंक

निर्मल रानी

स्वयंभू हिन्दू राष्ट्रवादियों द्वारा गत एक दशक से देश के बहुसंख्यक समाज को भारत को 'हिन्दू राष्ट्र ' बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। देश के अनेक दक्षिणपंथी नेताओं से लेकर तमाम कथावाचक व संत समाज से जुड़े लोग इसी 'प्रोपेगण्डे ' को प्रचारित करने में जुटे हुये हैं। इसी हिन्दू राष्ट्र की दुहाई देकर समाज में धर्म के आधार पर नफ़रत फैलाई जा रही है। सत्ता संरक्षित नफ़रती लोग धर्म विशेष के विरुद्ध जमकर ज़हर उगल रहे हैं और इसी बहाने देश के बहुसंख्य समाज को हिंदुत्व के नाम पर संगठित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिस देश में सभी धर्मों के लोग सदियों से मिलकर रहते आ रहे हों उस देश के बहुसंख्य समाज को अब अल्पसंख्यक समाज का भय दिखाकर शेष बहुसंख्य समाज को एकजुट होने का पाठ केवल और केवल अपने राजनैतिक लाभ के लिए पढ़ाया जा रहा है। और इन्हीं दक्षिणपंथी शक्तियों द्वारा इसी हिन्दू राष्ट्रवाद के नाम पर छेड़ी गयी मुहिम के मध्य, देश के उस संविधान को भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है जो भारतवसियों को समानता, समरसता,समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है। साथ ही इन्हीं स्वयंभू हिन्दू राष्ट्रवादियों द्वारा विवादित मनुस्मृति को भातीय संविधान के रूप में थोपे जाने की वकालत भी की जा रही है। यह शक्तियां उसी मनुस्मृति को देश पर थोपने के लिये प्रयासरत हैं जिसे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड में सार्वजनिक रूप से जलाया था। मनुस्मृति का विरोध करने वाले लोग आज भी उस ऐतिहासिक दिन को %मनुस्मृति दहन दिवस% के रूप में याद करते हैं। डॉ अंबेडकर ने मनु स्मृति का दहन इसलिये किया था क्योंकि यह ग्रंथ सामाजिक असमानता और जाति व्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाली शिक्षाओं को बढ़ावा देता है । जबकि मनु स्मृति का विरोध व इसके दहन का उद्देश्य दलितों और शोषित वर्गों के लिए समानता और न्याय की मांग को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करना था। सवाल यह है कि दक्षिणपंथियों द्वारा जिस मनुस्मृति की पैरवी की जा रही है क्या वह हिन्दू राष्ट्रवादियों द्वारा दिखाये जा रहे हिन्दू राष्ट्र निर्माण के स्वप्न को पूरा करने में सहायक साबित हो सकती है ? यदि हाँ तो पहला सवाल तो यही की बाबा साहब जैसी शख़्सियत को इसे जलाने की नौबत ही क्यों आई ? और दूसरे यह कि आख़िर हिन्दू धर्म में वह कौन सी व्यवस्था थी जिसका विरोध करते हुये डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन समारोह में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और इस सामूहिक धर्म परिवर्तन समारोह में डॉ. आंबेडकर के साथ उनके लगभग 3,80,000 अनुयायियों ने जिनमें मुख्य रूप से दलित समुदाय के लोग शामिल थे, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आज भी इस सामूहिक धर्म परिवर्तन को भारत में सामाजिक समानता और दलित आंदोलन का एक महत्वपूर्ण क़दम माना जाता है। परन्तु दु:ख का विषय तो यह है कि शोषित वर्ग द्वारा किये गये इस धर्म परिवर्तन के बावजूद आज भी मनुवादियों की सोच में कोई अंतर नहीं आया है। बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह जातिवादी विचारधारा गत दस वर्षों में और भी सिर चढ़ कर बोलने लगी है। और तो और अब इस जातिवादी सोच का शिकार केवल दलित समाज के लोग ही नहीं बल्कि पिछड़ी जातियों के लोग भी होने लगे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण पिछले दिनों उत्$र प्रदेश के इटावा ज़िले में केवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में देखने को मिला। यहाँ भागवत कथा कहने आए यादव समाज से सम्बन्ध रखने वाले एक कथावाचक भागवताचार्य व्यास मुकुट मणि के साथ ब्राह्मण समाज के लोग अत्यंत क्रूरता से पेश आये। कथावाचक को अपमानित किया उनके साथ मारपीट की और उनकी चोटी काटकर इस क्रूरता का वीडियो भी वायरल कर दिया गया। उनका क़ुसूर यही बताया गया कि कथा वाचन कर रहे व्यास, ब्राह्मण समुदाय के नहीं थे इसलिए उनकी चोटी काट दी गई और उनका वीडियो वायरल किया गया। इतना ही नहीं बल्कि बाल काटने के बाद 5 घंटे तक उन्हें बंधक बनाकर भी रखा गया। जातिवादी क्रूरता का अध्याय यहीं समाप्त नहीं हुआ बल्कि पीड़ित कथावाचक के अनुसार भागवत कथा के दौरान जो ब्राह्मण महिला परीक्षित थी, उसके पैरों पर कथावाचक की जबरन नाक रगड़वाई गई और उसी ब्राह्मण महिला के मूत्र से उस पर छिड़काव भी किया गया। उस पंडितानी महिला का मूत्र छिड़कने के बाद इन जातिवादियों द्वारा उससे कहा गया कि %ब्राह्मण का मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया अब तुम पवित्र हो गए%। ज़रा सोचिये कि कौन सी शिक्षा व संस्कार हैं जो इस क्रूरता के लिये जाति विशेष के लोगों दूसरी जातियों के विरुद्ध प्रोत्साहित करते हैं ?

दलितों के साथ तो ऐसी घटनाएं गोया आम बात हो चुकी हैं। पिछले दिनों ऐसी ही एक ह्रदय विदारक घटना उड़ीसा में हुई जहाँ गोतस्करी का आरोप लगाकर कुछ जातिवादी गुंडों द्वारा पहले तो उनसे पैसे वसूलने की कोशिश की गयी। जब दलित युवक पैसे देने में असमर्थ हुये तो उन दोनों युवाओं को 2 किलोमीटर तक घुटने के बल चलने के लिये मजबूर किया गया। इनके सर के बाल भद्दे तरीक़े से काटे गये उन्हें मारा पीटा गया ,उनके कपड़े फाड़े गये, उन्हें घास फूस खिलाई गयी। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें नाले का गन्दा पानी पीने के लिए भी मजबूर किया गया। इस तरह की घटनाएं भी आम हो चुकी हैं। अफ़सोस यह कि ऐसी क्रूर सोच व घृणित संस्कार रखने वाले लोगों को अनेक संतों व नेताओं का समर्थन भी मिल जाता है और वह मनुस्मृति जैसे जातिवादी धर्म ग्रंथों व संहिताओं से ही ढूंढ कर इन जातिवादियों के पक्ष में तर्क भी पेश कर देते हैं। और ऐसे ही जातिवादी लोगों के पैरोकार व समर्थक ही हिन्दू राष्ट्र व हिन्दू एकता जैसी विरोधाभासी बातें भी करते हैं।

और इससे भी बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि यह शक्तियां अपनी कुरीतियां छुपाने के लिये अपने धर्म ग्रंथों व संहिताओं का ज़िक्र करने के बजाये मुग़लों का नाम लेने लग जाती हैं। यानी एक ओर तो यह हिन्दू धर्म व संस्कृति को विश्व का सबसे प्राचीन धर्म बताते हैं जिसमे वर्ण व्यवस्था का ज़िक्र और इस व्यवस्था का महिमामंडन जगह जगह किया गया है दूसरी ओर मात्र 1400 वर्ष पुराने इस्लाम धर्म पर अपनी जातिवादी व्यवस्था का ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल स्वयंभू उच्च जाति वालों की यह एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत यह लोग हिन्दू राष्ट्र का ढोल पीटते रहते हैं इसी बहाने हिन्दू समाज को एकजुट कर इनका राजनैतिक लाभ उठाने की भी कोशिश करते हैं। परन्तु इनके ग्रन्थ व संस्कार इन्हें जातिवाद का आतंक फैलाने से रोक नहीं पाते।

जिम्मेदार कौन ?

प्रिय पाठकों आप भी एक पत्रकार हो तथा **दैनिक इंडिया वार्ता** की आवाज बन सकते हैं। बस आपको इसके लिए जरूरत है कि हर समय अपनी आंख व कान खुली रखें। चौंकन्ने रहें कि आपके चारों ओर क्या कुछ घटित हो रहा है। नाबालिग बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं? स्कूल बंक कर रहे हैं? विकास कार्यों में गड़बडी हो रही है? निर्माण कार्य महीनों से अधूरे पड़े हैं, पाइप लाइन टूटी हैं, घरों में दूषित पेयजल आपूर्ति या महिनों से पानी नहीं आ रहा है। मनरेगा में धांधली हो रही है? आपकी इस प्रकार की समस्याओं को **दैनिक इंडिया वार्ता** जिम्मेदार कॉलम में प्रमुखता के साथ उठाएगा? बस आप उठाइए कलम और तुरंत लिखकर हमें भेजें या फिर संपर्क करें? आपकी आवाज को सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों एवं सम्बन्धित अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा तथा इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल कराने का प्रयास भी किया जाएगा।

संपर्क करें
संपादक
दैनिक इंडिया वार्ता
प्रधान कार्यालय : मोहक्कमपुर खुर्द पोस्ट आई.आई.पी. रेलवे क्रसिंग
हरिद्वार रोड़ देहरादून (उत्तराखण्ड)
मोबाईल न.- 7500581414,9359555222
Email: indiawarta@gmail.com

देहरादून: टिहरी बांध पुनर्वास में भूमि धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा, DM ने कसे अधिकारियों पर शिकंजा

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने टिहरी बांध पुनर्वास योजना में चल रहे एक बड़े भूमि धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया है। एक ही व्यक्ति द्वारा टिहरी बांध प्रभावितों को दो बार जमीन बेचने का गंभीर मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने पुनर्वास परियोजना के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने विस्थापितों की मजबूरी और पीड़ा का फायदा उठाने वाले अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

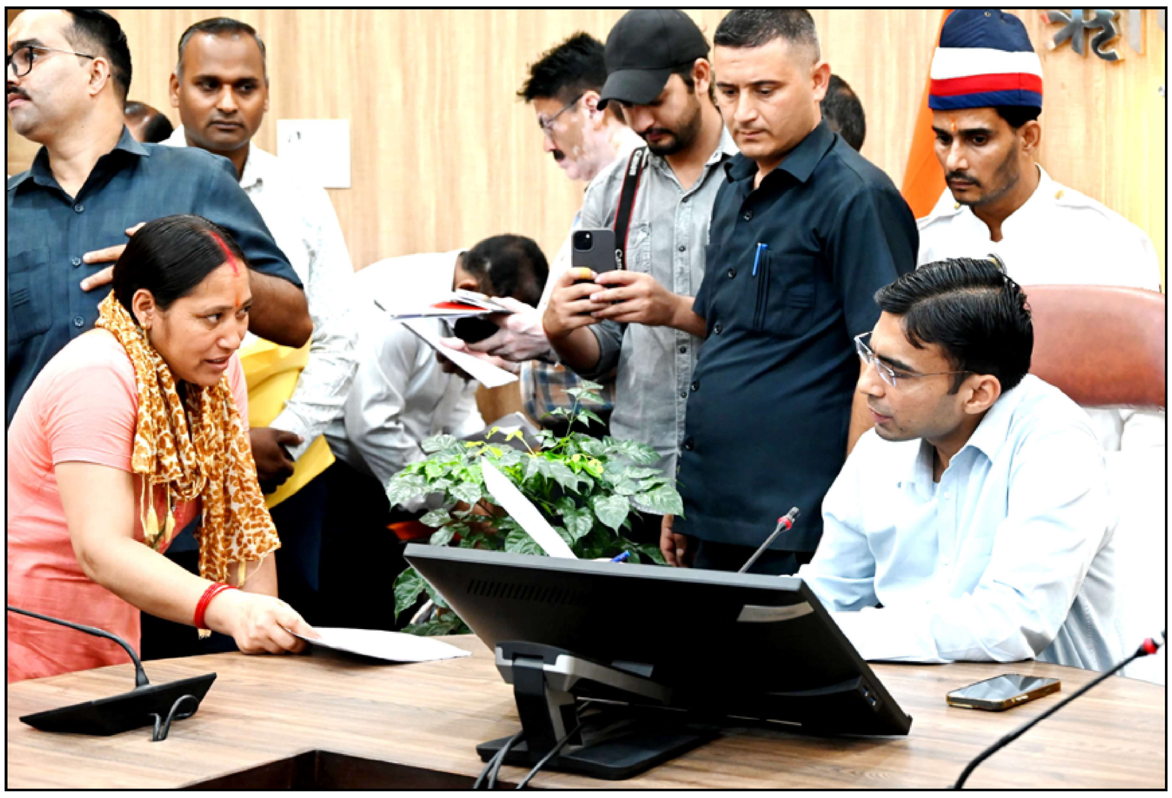

पुलमा देवी प्रकरण: DM ने खोली परतें, अवस्थापना पुनर्वास खंड ऋषिकेश का 'कारनामा'

यह मामला शास्त्रीनगर, तपोवन निवासी पुलमा देवी की शिकायत के बाद सामने आया, जो उन्होंने जून माह के दूसरे जनता दर्शन कार्यक्रम में जिलाधिकारी के समक्ष रखी थी। पुलमा देवी ने बताया कि उन्होंने 2007 में फुलसनी में एक आवासीय भूमि खरीदी थी, जिसकी विधिवत रजिस्ट्री भी हुई थी। यह भूमि टिहरी विस्थापितों को आवंटित की गई थी। लेकिन, चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 में भूमि स्वामी ने वही जमीन किसी और को बेच दी।

जिलाधिकारी द्वारा कराई गई गहन जांच में पता चला कि यह पूरा फर्जीवाड़ा अवस्थापना पुनर्वास खंड ऋषिकेश की मिलीभगत से हुआ है। जांच में खुलासा हुआ कि एक व्यक्ति, चंदरू पुत्र अमरू, जिसने अपनी जमीन (ग्राम फुलसनी, खसरा नंबर 399 च0मि0 में 200 वर्गमीटर भूखंड, आवासीय भूखंड सं. 44) मार्च 2007 में ही बेच दी थी और अप्रैल 2007 में कब्जा भी दे दिया था, उसी के नाम पर बिना किसी उचित जांच के 2019 में दोबारा भूमिधरी चढ़ा दी गई।

वरिष्ठ प्रबंधक (पुनर्वास), टिहरी बांध परियोजना, केदारपुर, देहरादून ने अपने पत्र में स्वीकार किया कि चंदरू ग्राम बंद्राकोटी ने विभाग को गुमराह करते हुए वास्तविक तथ्यों को छिपाया और उक्त भूखंड पर दोबारा भूमिधरी दिए जाने का प्रत्यावेदन किया था। इसी के फलस्वरूप उप राजस्व अधिकारी, अवस्थापना (पुनर्वास) खंड ऋषिकेश ने 2019 में भूमिधरी प्रकरण तहसील विकासनगर देहरादून को भेजा और भूमिधरी दोबारा अंकित कर दी गई।

DM का सख्त रुख: आपराधिक कार्यवाही और SIT जांच की चेतावनी

इस गंभीर धोखाधड़ी पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने तत्काल अधीक्षण अभियंता (टिहरी बांध पुनर्वास) का वाहन जब्त करने का आदेश दिया है और उन्हें विवरण सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को एसआईटी जांच में संस्तुति की भी चेतावनी दी है, जो दर्शाता है कि प्रशासन इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतने वाला।

डीएम ने इस प्रकरण की विस्तृत आपराधिक कार्यवाही (क्रिमिनल प्रोसीडिंग) के लिए जांच उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा को सौंपी है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जब तक पुलमा देवी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक प्रशासन इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है। जिला प्रशासन ने इस प्रकरण पर सख्त एक्शन का मन बना लिया है और भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए भी कमर कस ली है। इस मामले में अभी भी मा. सिविल जज (जू.डि.) विकासनगर, देहरादून में पुलमा देवी बनाम जतिन गोयल पुत्र राजरानी के बीच भूमि का वाद विचाराधीन है। जिलाधिकारी की इस त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से टिहरी बांध पुनर्वास परियोजना में पारदर्शिता लाने और विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा करने की उम्मीद जगी है।

देहरादून में DM सविन बंसल की पहल से विकास कार्यों को मिली गति: CM के विजन को ज़मीन पर उतारने में जुटे

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इन दिनों विकास कार्यों में अभूतपूर्व तेज़ी देखी जा रही है. जिलाधिकारी सविन बंसल के अथक प्रयासों और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, शहर की कई महत्वपूर्ण योजनाएं न केवल समय पर धरातल पर उतर रही हैं, बल्कि समस्याओं का त्वरित समाधान भी हो रहा है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है. जिला प्रशासन का फोकस अब सिर्फ़ योजना बनाने पर नहीं, बल्कि उन्हें रिकॉर्ड समय में क्रियान्वित करने पर है.

मंथन से पहले क्रियान्वयन: डीएम सविन बंसल का अभिनव दृष्टिकोण

सामान्यत: किसी भी बड़ी परियोजना में कागज़ी कार्यवाही, विचार-विमर्श और वाद-विवाद में लंबा समय लगता है, लेकिन देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में यह धारणा बदलती दिख रही है. मुख्यमंत्री के दूरदर्शी विजन से प्रेरित होकर, जिला प्रशासन अब योजना, डिज़ाइन और धनराशि की व्यवस्था को एक साथ साधते हुए, उन्हें रिकॉर्ड समय में ज़मीन पर उतारने में जुटा है. उनकी कार्यप्रणाली में निरंतर प्रयास और समन्वय केंद्र में हैं, जिससे परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा किया जा रहा है.

शहर के सौंदर्यीकरण और यातायात प्रबंधन में क्रांति

देहरादून को एक सुंदर, पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर के रूप में संवारने के लिए कई अभिनव कार्य किए जा रहे हैं. साई मंदिर जंक्शन, कुठालगेट और दिलाराम चौक का पहाड़ी शैली में सौंदर्यीकरण कार्य अंतिम चरण में है. इन चौराहों पर राज्य की सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाती कलाकृतियों का प्रयोग किया जा रहा है, जो देहरादून आने वाले पर्यटकों को यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएंगी.

यातायात प्रबंधन भी जिला प्रशासन की प्राथमिकता में है. कुठालगेट और साई मंदिर पर नई स्लिप रोड का कार्य और राउंडअबाउट लाइटिंग के साथ पारंपरिक शैली में निर्मित चौराहों का विस्तार कार्य भी अंतिम चरण में है. जिलाधिकारी ने इन नव निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी बजट से 10 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है.

सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था की ओर महत्वपूर्ण कदम

सड़क सुरक्षा और सुरक्षित यातायात के प्रति जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है. डीएम के निर्देश पर देहरादून के 11 प्रमुख जंक्शनों पर नई ट्रैफिक लाइट लगाने का कार्य पूरा हो चुका है. इनमें महाराणा प्रताप चौक, नालपानी चौक, मोथोरावाला, आईटी पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर शामिल हैं. प्रेमनगर चौक, सुधोवाला चौक, रांगड़वाला, धूलकोट तिराहा, सेलाकुई बाजार तिराहा और डाकपत्थर तिराहा पर भी यह कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा.

इसके अतिरिक्त, पिछले पाँच वर्षों में पहली बार प्रमुख चौराहों पर लगे पुलिस के सीसीटीवी कैमरों को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिससे सड़कों पर सुरक्षित यातायात की नियमित निगरानी की जा रही है.

जिलाधिकारी सविन बंसल ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बजट प्रबंधन में न केवल निर्माण, बल्कि योजना का दीर्घकालिक रखरखाव भी शामिल हो, जिससे परियोजनाओं की सार्थकता बनी रहे. देहरादून अब वास्तव में एक समर्पित विकास की ओर अग्रसर दिख रहा है.

डॉ. विश्वनाथ तिवारी ने चौथी बार आयरनमैन चैंपियनशिप पूरी की

नईदिल्ली,इंडिया वार्ता ब्यूरो। उत्तर रेलवे केन्द्रीय अस्पताल में कार्यरत ऑन्को सर्जन डॉ. विश्वनाथ तिवारी ने आयरनमैन फ्रैंकफर्ट यूरोपियन चैंपियनशिप 2025 में अपना चौथा आयरनमैन चैंपियनशिप खिताब पूरा करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस प्रतिष्ठित स्पर्धा को दुनिया की सबसे कठिन खेल गतिविधियों में से एक माना जाता है, जिसमें 3.86 कि.मी. तैराकी, 180 कि.मी. साइकिलिंग और 42 कि.मी.दौड़ शामिल है, जो सभी 15 घंटे के भीतर पूरी की जाती है। डॉ. तिवारी ने इस चुनौती को 14 घंटे और 3 मिनट में पूरा किया।

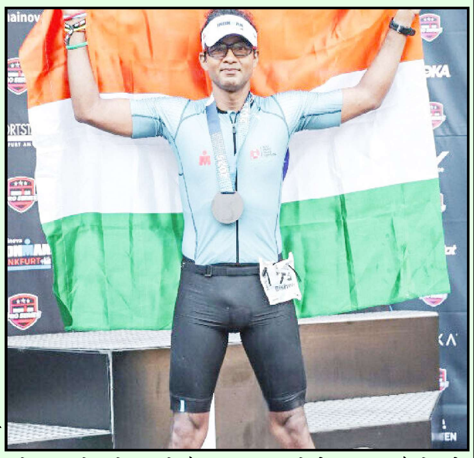

भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, डॉ. तिवारी ने बड़े गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज के साथ आयरनमैन के रेड कार्पेट पर शानदार एंट्री की। उनकी यह उपलब्धि न केवल एक व्यक्तिगत जीत है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।

डॉ. तिवारी की उपलब्धि उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं बढ़कर है । उनका मानना है कि नियमित खेल गतिविधियों से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मस्तिष्क और हृदय संबंधी स्ट्रोक और कई प्रकार के कैंसर जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है । अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर, डॉ. तिवारी समाज के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करते हैंऔरएक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं तथा दूसरों को भी ऐसी ही जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित भी करते हैं।

डॉ. तिवारी ने अपनी आयरनमैन चैंपियनशिप भारतीय रेलवे और भारत के लोगों को समर्पित की,जो राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत की वैश्विक पहचान : घाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अब तक 24 देशों ने किया सम्मानित

नईदिल्ली,एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती साख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक कुशलता ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसका ताजा उदाहरण जुलाई में घाना की राजधानी अक्रा में देखने को मिला, जहां पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान %ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' से नवाजा गया।

यह सम्मान विदेशी नेताओं को बहुत कम दिया जाता है और यह भारत-घाना के मजबूत रिश्तों का प्रतीक है।

30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना यात्रा ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा किया।

घाना की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और घाना का रिश्ता सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपसी विश्वास और साझा मूल्यों की नींव पर टिका है। यह सम्मान भारत की जनता के लिए गर्व का क्षण है।

उन्होंने भारत-अफ्रीका सहयोग, सांस्कृतिक जुड़ाव और विकास की साझा यात्रा पर जोर दिया।

पीएम मोदी को अब तक 24 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, जो किसी भी भारतीय नेता के लिए रिकॉर्ड है।

इनमें रूस का %ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू', यूएई का %जायद मेडल', फ्रांस का %ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर', मालदीव का %रूल ऑफ इज्जुद्दीन' और नाइजीरिया, साइप्रस, फिजी जैसे देशों के प्रतिष्ठित पुरस्कार शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने भी उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए %चैंपियन ऑफ द अर्थ' पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और प्रभाव का परिचायक हैं।

पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने %वसुधैव कुटुंबकम' की भावना को अपनाते हुए वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत किया है। उनकी विदेश यात्राएं नए व्यापारिक अवसर, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम बनी हैं।

घाना का यह सम्मान भारत के वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को रेखांकित करता है। पीएम मोदी ने न केवल भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, बल्कि वे विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। उनकी कूटनीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद और प्रभावशाली साझेदार बनाया है। यह सम्मान भारत के उभरते कद और विश्वास की गवाही है, जो आने वाले समय में और सशक्त होगा।

सीबीआई की बड़ी कार्रवाई : 6 राज्यों में 40 से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, 6 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में छह राज्यों में बड़ी कार्रवाई की है। कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान तीन डॉक्टरों सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर रिश्वत लेकर मेडिकल कॉलेजों को अनुकूल निरीक्षण रिपोर्ट देने का आरोप है।

सीबीआई ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों और बिचौलियों के खिलाफ की। आरोप है कि इन लोगों ने मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के लिए होने वाले वैधानिक निरीक्षण में हेरफेर किया। निरीक्षण करने वाले डॉक्टरों ने कथित तौर पर रिश्वत लेकर अनुकूल रिपोर्ट दी। सीबीआई को सूचना मिली थी कि संस्थान के पदाधिकारी निरीक्षकों को प्रभावित कर रहे थे। इसके आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया और 55 लाख रुपये की रिश्वत के लेन-देन के दौरान छह लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंडेक्स कॉलेज के प्रबंधक के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। यह कार्रवाई सुबह 3 बजे शुरू हुई और 8 बजे तक चली। सीबीआई ने इस ऑपरेशन को पूरी तरह गुप्त रखा और जानकारी को एक्स पर पोस्ट करके सार्वजनिक की। गिरफ्तार आरोपियों को संबंधित अदालतों में पेश किया जाएगा। सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने निरीक्षकों को रिश्वत देकर निरीक्षण प्रक्रिया में हेरफेर किया। रिश्वत की राशि बेंगलुरु में पहुंचाई गई थी। इस मामले में विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान जारी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच अभी चल रही है और जल्द ही महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को छह महीने की सजा का ऐलान, इस मामले में पाई गई दोषी

ढाका,एजेंसी। बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में छह महीने की कारावास की सजा सुनाई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तीन सदस्यीय ट्राइब्यूनल की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति गोलाम मुर्तुजा माजुमदार ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में अवामी लीग की छात्र इकाई %छात्र लीग' के नेता शकील अकांडा बुलबुल को भी दो महीने की सजा दी गई है। यह सजा सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप के आधार पर दी गई, जिसमें कथित तौर पर शेख हसीना को न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते और ट्राइब्यूनल को धमकी देते सुना गया था। इसके आधार पर ट्राइब्यूनल ने पिछले महीने हसीना और बुलबुल को शो-कॉज नोटिस जारी किया था। शेख हसीना अगस्त 2024 में देश छोड़कर चली गई थीं।

अवामी लीग ने इस पूरे मामले की निंदा करते हुए इसे एक शो ट्रायल (नकली मुकदमा) करार दिया और कहा कि यह सत्तारूढ़ अंतरिम सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध के तहत शुरू किया गया है। पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आईसीटी में निष्पक्ष सुनवाई और प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर जताई गई चिंता का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा प्रशासन ने केवल अवामी लीग नेताओं को निशाना बनाया है, जबकि आम नागरिकों, पत्रकारों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर हुए अत्याचारों को नजरअंदाज किया गया है। अवामी लीग ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के कई अधिकारी पहले ही सार्वजनिक मंचों पर शेख हसीना को दोषी ठहरा चुके हैं, जिससे निष्पक्ष सुनवाई की संभावना ही खत्म हो गई है।

गौरतलब है कि यह वही ट्राइब्यूनल है, जिसे शेख हसीना की सरकार ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों की जांच और सजा के लिए स्थापित किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सजा वर्तमान कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध की एक कड़ी है, जिसने शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के तुरंत बाद उन पर और उनके समर्थकों पर कई मामले दर्ज किए। शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और देश में लोकतंत्र की बहाली की एक प्रमुख आवाज रहे हैं।

होशियारपुर में तीन मंजिला मकान की छत गिरी, पिता समेत दो बेटियों की मौत

होशियारपुर ,एजेंसी पंजाब के होशियारपुर में तीन मंजिला घर की छत गिरने से पिता समेत 2 बेटियों की मौत हो गई है, जबकि पत्नी और अन्य 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हैं।

मामला होशियारपुर के टांडा क्षेत्र में स्थित आईयापुर मोहल्ले का है। बताया जा रहा है कि घर में प्रवासी मजदूर शंकर मंडल अपनी 4 बेटियों और पत्नी के साथ रहता था। शंकर मंडल मजदूरी करता था।

गुरुवार सुबह साढ़े 5 बजे के करीब अचानक पूरा घर ढह गया, जिसमें पूरा परिवार दब गया। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मलबे में फंसे परिवार के लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे में शंकर मंडल और उसकी 2 बेटियां, शिवानी और पूजा की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और 2 अन्य बेटियां घायल हो गईं, जिन्हें जख्मी हालत में टांडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मकान मालिक विकास कुमार ने बताया कि मकान की हालत काफी जर्जर थी। मैंने परिवार को बताया था कि मकान की स्थिति खराब है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ दिनों के लिए मकान को किराए पर रहने के लिए ले लिया। इस हादसे में परिवार के तीन सदस्यों की मौत हुई है और तीन घायल हैं। टांडा के एसएचओ ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि हमें सुबह साढ़े पांच बजे मकान के ढहने की सूचना मिली थी। हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है और तीन घायल हैं। इस मकान की स्थिति काफी जर्जर थी, इसी कारण ये हादसा हुआ। टांडा के सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर ने कहा कि सुबह साढ़े सात बजे के आसपास तीन मरीजों को एंबुलेंस के माध्यम से लाया गया था, जिनमें से पिता और बेटी की मौत हो चुकी थी, जबकि पत्नी की हालत गंभीर है।

फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

नाम पट मामले में पुनर्विचार करे धामी सरकार : राजीव महर्षि

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी महर्षि ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पारित किए गए नाम पट अनिवार्यता के आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए इस तुगलकी फरमान को तत्काल वापस लेने की मांग की है। एक बयान में महर्षि ने कहा कि कारोबार कर रहे किसी भी व्यक्ति को नाम बताने में क्या हर्ज हो सकता है लेकिन अगर कांवड़ जैसी पवित्र और श्रद्धाभक्ति पूर्ण यात्रा के मार्ग पर गलत मंशा से ऐसा करने का आदेश जारी किया जा रहा है तो यह गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश समझ से परे है और यह समाज की समरसता को खंडित करने का प्रयास प्रतीत हो रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से एक समुदाय विशेष का आर्थिक बहिष्कार करने के बयान कुछ छोटे बड़े नेताओं के आते रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि नाम जानने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार यही नियम जम्मू कश्मीर अथवा उत्तर पूर्व में लागू करना चाहेगी? इस मुद्दे पर भी लोग भाजपा की मंशा जानना चाहते हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर यूसीसी की बात करने वाले अलग – अलग प्रदेश में अलग अलग नीति कैसे अपना सकते हैं? उन्होंने पूछा है कि क्या नार्थ ईस्ट के लिए भी यह नियम लागू किया जायेगा?

मीडिया प्रभारी महर्षि ने पूछा है कि सरकार यह भी स्पष्ट करे कि यदि नाम बताने के नियम से समुदाय विशेष के व्यापार को नुकसान होता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी?

उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटका कर देश को गैर जरुरी मुद्दों की ओर धकेला जा रहा है?

महर्षि ने कहा कि उत्तराखंड इस समय गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। आए दिन सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है, सैकड़ों मार्ग अवरुद्ध हैं लेकिन आलवेदर रोड का नारा देने वाली सरकार का ध्यान पीड़ितों की ओर न होकर इस गैर जरूरी मुद्दे पर केंद्रित है। सरकार की प्राथमिकता आपदा पीड़ित प्रदेश के लोगों को राहत पहुंचाने की होनी चाहिए लेकिन इस गैर जरूरी मुद्दे को आगे बढ़ा रही है जबकि यह समाज के लिए विभाजनकारी आदेश है। उन्होंने समय रहते सरकार से तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग की है।

कौसानी के लक्ष्मी आश्रम में राधा बहन को पद्मश्री से किया गया सम्मानित

जिलाधिकारी ने स्वयं आश्रम पहुंचकर किया अलंकरण, बच्चियों को भी दी प्रेरणा

अल्मोड़ा (इंडिया वार्ता ब्यूरो)। भारत सरकार द्वारा अल्मोड़ा जनपद की प्रख्यात गांधीवादी समाजसेवी राधा बहन को दिए गए पद्मश्री सम्मान को आज औपचारिक रूप से उनके कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम में प्रदान किया गया। स्वास्थ्य कारणों के चलते वे सम्मान ग्रहण करने दिल्ली नहीं जा सकी थीं, ऐसे में जिलाधिकारी अल्मोड़ा ने स्वयं आश्रम पहुंचकर उन्हें यह सम्मान सौंपा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आश्रम में अध्ययनरत बालिकाओं से संवाद किया और उन्हें राधा बहन के विचारों और जीवन-शैली से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने की सीख दी। उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूँ कि इस आश्रम से और भी पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले निकलें, जो समाज सेवा और देशहित में उल्लेखनीय योगदान दें। यात्रा के दौरान आश्रम मार्ग में एक स्थान पर पेड़ों की कटाई और भूमि कटाव को देखकर जिलाधिकारी ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम के अवसर पर अपर जिलाधिकारी सी. एस. मर्तोलिया, तहसीलदार नेहा धपोला, जनमेजय तिवारी, श्रीश कपूर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मुम्बई क्राइम ब्रांच की उत्तराखण्ड में छापेमारी, अवैध मेफेड्रोन फैक्ट्री का पर्दाफाश

पिथौरागढ़, । ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र की ठाणे क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में नेपाल सीमा के पास चल रही अवैध मेफेड्रोन (एमडी) फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 30 लाख रूपये की ड्रग्स, मशीनरी, रसायन और वाहन जब्त किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई कासरवडावली पुलिस स्टेशन, ठाणे में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले की जांच के बाद की गई। शुरुआती जांच में ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिटक्5 ने दो आरोपियों विशाल सिंह और मल्लेश शेवाला को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 10 ग्राम एमडी पाउडर बरामद हुआ जिसकी कीमत 35 हजार रूपये आंकी गई थी। पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया था कि यह नशीला पदार्थ उत्तराखंड से मंगवाया गया था। इस इनपुट पर पुलिस टीम को उत्तराखंड भेजा गया, जहां 27 जून को पिथौरागढ़ के एक निर्माणाधीन फैक्ट्री पर छापा मारा गया। छापेमारी में 18 लाख रूपये से अधिक के ड्रग्स बनाने वाले रसायन, उपकरण और मशीनें बरामद हुई। छापे से पहले आरोपी मौके से फरार हो गए थे और नेपाल सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 28 जून को स्थानीय पुलिस और नेपाल सीमा सुरक्षा बल की मदद से उन्हें पकड़ लिया गया। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 5 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ओम गुप्ता और अमर कोहली इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी मेफेड्रोन बनाने के अवैध कारोबार में शामिल थे। कासरवडावली पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ पहले से एक एफआईआर दर्ज है और दोनों आरोपी वहां से फरार चल रहे थे।

आईजी कुमाऊं रेंज रिद्धिम अग्रवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस की सहायता से यह कार्रवाई सफल हुई है। उन्होंने बताया कि अब पूरे कुमाऊं रेंज में ड्रग्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में पहली बार इस तरह की बड़ी मेफेड्रोन फैक्ट्री के भंडाफोड़ से यह स्पष्ट हो गया है कि सीमावर्ती क्षेत्र अब ड्रग माफियाओं के निशाने पर हैं।

राशा ठडानी ने ढाया कहर, फैंस बोले कितनी प्यारी लग रही हो

रवीना टंडन की बेटी राशा ठडानी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस अवतार से तहलका मचा दिया है. राशा ने हाल ही में एक फोटोशूट कराया जिसमें वह शाइनी सिल्वर बॉडीकॉन गाउन में नजर आ रही हैं. इस एलिगेंट और बोल्ड लुक को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है, जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा - रजत मंत्र. राशा की इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस दीवाने हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा, कितनी प्यारी, तो दूसरे ने कहा, राशू क्या आपको नहीं लगता कि 11वीं तस्वीर आपकी प्रोफाइल तस्वीर होनी चाहिए? वहीं किसी ने तो यहां तक कह दिया कि किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया!! जी करे देखत रहु. राशा का ये ग्लैमरस लुक न सिर्फ उनकी फिटनेस को हाईलाइट करता है बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी झलकाता है. खुले बाल, मिनिमल मेकअप और परफेक्ट पोज़ - हर एंगल से वह कमाल लग रही हैं. कुछ ही मिनटों में इस पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं, और यह तेजी से वायरल हो रहा है. राशा ठडानी अब बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही हैं और इंडस्ट्री में उनकी मौजूदगी पहले से ही चर्चा में बनी हुई है. उनके स्टाइल सेंस, सोशल मीडिया अपील और ग्रेस को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह आने वाले समय की एक बड़ी स्टार बन सकती हैं.

गंगा पुस्तक परिक्रमा में छात्रों के बीच किया कथा-वाचन

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित गंगा पुस्तक परिक्रमा के पुस्तक वाहन ने गुरुवार को दून स्थित सनराइज अकादमी में पड़ाव डाला। गोमुख से लेकर गंगासागर तक चलने वाली इस वार्षिक पुस्तक परिक्रमा के अंतर्गत पठनीयता को बढ़ावा देने, नई पीढ़ी में साहित्यिक संस्कार रोपने और सृजनात्मकता को परिष्कृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को वरिष्ठ साहित्यकार मुकेश नौटियाल और स्कूली छात्र-छात्राओं का संवाद आयोजित किया गया। जिसमें उन्होंने बच्चों को गंगा और गंगा से जुड़े प्रांतों की पारिस्थितिकी और जनजीवन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने छात्रों को हिमालयी अंचल पर केंद्रित अपनी कहानियां सुनाई। बच्चों ने लेखक से उनकी कहानियों के शिल्प और उनकी लेखन-यात्रा पर कई सवाल पूछे। बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नेशनल बुक ट्रस्ट के आकाश अत्रि, देवी सिंह, स्कूल की प्रिंसिपल नीतू तोमर, प्रधान प्रबंधक पूजा पोखरियाल और शिक्षकों के अलावा साहित्य, संस्कृति, कला प्रेमी और बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे।

एसएसआई मंत्रा एम 'मेड इन इंडिया' सर्जिकल रोबोट यात्रा ने शुरू किया अपना भारत दौरा

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । भारत के पहले और एकमात्र स्वदेश में विकसित सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा के निर्माता एसएस इनोवेशन्स ने आज गुरुग्राम स्थित अपने मुख्यालय से एसएसआई मंत्रा एम 'मेड इन इंडिया' सर्जिकल रोबोट यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रोडशो का उद्घाटन हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नारबीर सिंह ने किया। एसएसआई मंत्रा एम सर्जिकल रोबोट यात्रा के साथ भारत ने हेल्थकेयर में एक बदलावकारी यात्रा की शुरूआत की है, जिसके तहत पहली मोबाइल रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग एवं डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट का अनावरण भी किया गया। यह आधुनिक 'टेलीसर्जरी-ऑन-व्हील्स' पहल आधुनिक सर्जिकल टेक्नोलॉजी एवं कौशल निर्माण के अवसरों को सीधे देश के अस्पतालों और हेल्थकेयर पेशेवरों तक लेकर आई है। स्वदेश में विकसित यह यूनिट रियल-टाईम कोलाबोरेशन को सक्षम बनाती है तथा एसएसआई मंत्रा सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम के आधुनिक फीचर्स एवं क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। लाईव सिमुलेशन्स, इंटरैक्टिव ट्रेनिंग मोड्यूल्स एवं गाइडेड डेमो के ज़रिए यह सर्जन, मेडिकल के छात्रों एवं हेल्थकेयर पेशेवरों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। यह पहल भारत में रोबोटिक सर्जरी के बारे में जागरुकता और स्वीकार्यता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है- खासतौर पर आधुनिक सर्जिकल टेक्नोलॉजी को टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में अधिक सुलभ बनाएगा।

राजस्थान में अपने पहले चरण के तहत एसएसआई मंत्रा एम की यात्रा 3 एवं 4 जुलाई को एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से शुरू होगी, जहां चिकित्सा समुदाय के लिए लाईव डेमो एवं इंटरैक्टिव ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। 4 जुलाई दोपहर को मंत्रा एम एम्स जोधपुर पहुंचेगा। 6 जुलाई तक यात्रा रफकोन में हिस्सा लेगी। 6 जुलाई की शाम यह मथुरा दास माथुर मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना होगा, जहां 7 जुलाई को सत्र आयोजित किए जाएंगे। 8 जुलाई को राजस्थान लैग का समापन का अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में होगा, इसके बाद यह यात्रा वापस गुरुग्राम आएगी। मंत्रा एम 'मेड इन इंडिया' सर्जिकल रोबोट यात्रा की शुरूआत पर बात करते हुए डॉ सुधीर श्रीवास्तव, संस्थापक चेयरमैन एवं सीईओ, एसएस इनोवेशन्स ने कहा, ''एसएसआई मंत्रा एम एक मोबाइल रोबोटिक ट्रेनिंग एवं डेमोन्स्ट्रेशन युनिट से कहीं बढ़कर है, यह विश्वस्तरीय सर्जिकल शिक्षा एवं इनोवेशन को सुलभ बनाने का एक राष्ट्रीय आंदोलन है। मल्टी-सिटी रोडशो की शुरूआत के साथ यह हेल्थकेयर की भोगोलक बाधाओं को दूर करते हुए सर्जिकल रोबोटिक्स में भारत की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करता है। वंचित एवं दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन की गई यह युनिट आधुनिक टेलीकम्युनिकेशन क्षमता से युक्त है तथा भावी सैटेलाईट कनेक्टिविटी के लिए अनुसंधान एवं विकास का काम जारी है। जिसके द्वारा इसे देश के सबसे सुदूर इलाकों में भी रियल-टाईम टेली सर्जरी के लिए फ्यूचर-रैडी बनाया जा सकता है। वर्तमान में यह रोडशो डॉक्टरों एवं हेल्थकयर पेशेवरों को लाईव डेमो, व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं इंटरैक्टिव सत्रों के ज़रिए सीधे एसएसआई मंत्रा सिस्टम के साथ जोड़ेगा। एसएसआई मंत्रा एम तकनीकी क्षमता के प्रदर्शन से बढ़कर भविष्य के लिए ऐसा दृष्टिकोण पेश करता है जहां आधुनिक रोबोटिक सर्जरी सुलभ एवं समावेशी हो जाएगी। ये प्रयास हेल्थकेयर में बदलाव लाने के एसएस इनोवेशन्स के मिशन की पुष्टि करते हैं। राव नारबीर सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, हरियाणा सरकार ने कहा, हमारे लिए गर्व की बात है कि एसएस इनोवेशन्स हरियाणा की कंपनी है। एसएसआई मंत्रा एम 'मेड इन इंडिया' सर्जिकल रोबोट यात्रा हमारे देश के तकनीकी एवं मेडिकल इनोवेशन का बेहतरीन उदाहरण है। इस पहल से न सिर्फ देश में हेल्थकेयर डिलीवरी के मानक बेहतर होंगे बल्कि टियर 2 एवं टियर 3 शहरों के डॉक्टर एवं मेडिकल संस्थान आधुनिक टूल्स एवं प्रशिक्षण के साथ सशक्त बनेंगे। मैं एसएस इनोवेशन्स के दूरदृष्टा प्रयासों के लिए उनकी सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने आधुनिक सर्जिकल केयर को अधिक सुलभ बनाकर भारत को दुनिया के मानचित्र पर हेल्थकेयर इनोवेशन के हब के रूप में स्थापित किया है।

मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने ऐतिहासिक एकीकृत विनिर्माण इकाई का किया उद्घाटन

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो । दुनिया के पांचवें सबसे बड़े खुदरा आभूषण विक्रेता (ज्वेलरी रिटेलर) मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, तेलंगाना में अत्याधुनिक, पूरी तरह से एकीकृत (इंटीग्रेटेड) आभूषण विनिर्माण इकाई (ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट) की शुरुआत की है. यह इकाई अपनी तरह की सबसे बड़ी है। मलाबार गोल्ड के 13 देशों में 400 से ज्यादा शोरूम हैं। इस इकाई की शुरुआत को लेकर मलाबार ग्रुप के चेयरमैन एम पी अहमद ने कहा, हैदराबाद में हमारी अत्याधुनिक आभूषण विनिर्माण इकाई, जो परंपरा, कला, आधुनिकता और परिशुद्धता का संयोजन करती है, आभूषण विनिर्माण में एक नए युग की शुरुआत है। यह इकाई हमारे 'मेक इन इंडिया, मार्केट टू द वर्ल्ड' दृष्टिकोण के अनुरूप वैश्विक बाजारों के लिए भारत में विश्वस्तरीय आभूषण तैयार करने की हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है।

क्लस्टर योजना बनी छात्रों-अभिभावकों के लिए 'जी का जंजाल', जन संघर्ष मोर्चा ने सरकार पर साधा निशाना

इंडिया वार्ता ब्यूरो

विकासनगर । उत्तराखंड में हाल ही में लागू की गई क्लस्टर योजना छात्रों और अभिभावकों के लिए नई मुसीबत लेकर आई है। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने इस योजना को %तुगलकी फरमान% बताते हुए सरकार और शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आनन-फानन में बिना किसी ठोस तैयारी और जमीनी हकीकत जाने यह योजना लागू कर दी गई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि क्लस्टर योजना के तहत लगभग 559 इंटरमीडिएट विद्यालयों को मुख्य केंद्र (क्लस्टर विद्यालय) घोषित कर ढाई हजार से अधिक विद्यालयों को इनमें शामिल किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना क्लस्टर विद्यालयों को पर्याप्त संसाधनों से लैस किए यह महत्वाकांक्षी मिशन कैसे सफल हो सकता है? नेगी ने अभिभावकों और छात्रों के गुस्से को साझा करते हुए कहा कि आखिर छात्र अपने मूल विद्यालयों को छोड़कर, जहां उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है, 5-7 या 10-15 किलोमीटर दूर स्थित इन क्लस्टर विद्यालयों में दाखिला क्यों लेंगे?

मोर्चा अध्यक्ष ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या 150-200 है, उन्हें भी क्लस्टर विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके विपरीत, जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या पहले से अच्छी खासी है, उन्हें ही सुविधाओं से संपन्न कर क्लस्टर विद्यालय बनाया जाना चाहिए, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

नेगी ने इस पूरी कवायद को %आनन-फानन% में की गई कार्रवाई बताते हुए खंड स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने बिना भौतिक सत्यापन किए, छात्रों की वास्तविक संख्या और अन्य महत्वपूर्ण आधारों की जांच किए बिना ही उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी, जिसके आधार पर ये %तुगलकी फरमान जारी किए गए।

जन संघर्ष मोर्चा का मानना है कि क्लस्टर योजना एक अच्छी पहल हो सकती थी, लेकिन तथ्यों की पड़ताल किए बिना इसे लागू करने से यह छात्रों और अभिभावकों के लिए %जी का जंजाल% बन गई है। नेगी ने सुझाव दिया कि यह योजना उन क्षेत्रों में लागू की जा सकती थी जहां छात्रों की संख्या काफी घट गई है। उन्होंने विभागीय मंत्री से इस मामले में सक्रिय रूप से मॉनिटरिंग न करने पर भी सवाल उठाए। मोर्चा ने स्पष्ट किया कि वे इस %तुगलकी फरमान% को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द ही इस मामले को शासन के समक्ष उठाएंगे। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार और प्रवीण शर्मा पिन्नी भी मौजूद रहे।

प्रथम पृष्ठ का शेष — मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों के साथ की ..

की शिकायत आने पर संबंधित होटल स्वामियों पर शक्ति से करवाई की जाए। उन्होंने कहा शराब तथा मीट से संबंधित एसओपी का भी इस दौरान सख्ती से पालन हो।

मुख्यमंत्री ने कहा इस वर्ष हमने क्लीन और ग्रीन कांवड़ यात्रा का संदेश देना है। उन्होंने कहा स्वच्छता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिसके लिए संपूर्ण कावड़ मार्गो पर हर घंटे सफाई अभियान चलता रहे। हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और आस पास के क्षेत्रों में हर 1-2 किलोमीटर पर मोबाइल टॉयलेट, कूड़ा निस्तारण के लिए विशेष गाड़ियों की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कांवड़ रूट पर हर 2 से 3 किलोमीटर के अंदर स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएं, जिससे आम जन को सहूलियत हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कावड़ियों की सुविधा को देखते हुए स्थानीय निकायों के सहयोग से रैन बसेरों, टेंट सिटी, आश्रय स्थलों का निर्माण किया जाए। यात्रा मार्गो पर आर.ओ टैंकर, वाटर एटीएम की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा बीते सालों के अनुभवों के आधार पर पार्किंग की अतिरिक्त व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने कावड़ यात्रा से संबंधित सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं के लिए श्क्या करें और क्या नहीं करेंश् की जानकारी यात्रा मार्गो पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। सीसीटीवी और ड्रोन से नियमित निगरानी हो। कांवड़ रूट का जीआईएस मैपिंग आधारित ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाए और ए.आई आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एस.डी.आर.एफ, एन.डी.आर.एफ की तैनाती, बारिश और भूस्खलन की पूर्व चेतावनी प्रणाली सक्रिय की जाए। साथ ही संवेदनशील घाटों पर एनाउंसमेंट सिस्टम भी मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा संपूर्ण हरिद्वार क्षेत्र में खोया पाया केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाए

जिला अधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने बताया कि इस वर्ष कावड़ मेला 11 से 23 जुलाई तक आयोजित होगा। इस वर्ष मेले को कुल 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टर में बांटा गया है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोगों की सहूलियत अनुसार यातायात व्यवस्था की गई हैं। उन्होंने बताया चार धाम जाने वाले श्रद्धालु, स्थानीय लोगों एवं कावड़ यात्रियों के लिए अलग-अलग यातायात व्यवस्थाएं भी लागू की गई है।

बैठक में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, आदेश चौहान, ममता राकेश, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, मेयर किरण जेसल, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, डीजीपी श्री दीपम सेठ, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नितेश झा, पंकज पांडेय, विनोद कुमार सुमन, विनय शंकर पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनय रूहेला, दर्जा राज्यमंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि, शोभाराम प्रजापति, सुनील सैनी, श्यामवीर सैनी, जयपाल सिंह चौहान, देशराज कर्णवाल, श्री गंगा सभा अध्यक्ष नितिन गौतम, बीजेपी जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

प्रथम पृष्ठ का शेष — स्वच्छता अभियान में शामिल हुए सीएम ..

श्रद्धालुओं द्वारा अपने यात्रा अनुभव साझा करते हुए देवभूमि तथा व्यवस्थाओं को अच्छा बताया।

इस दौरान सांसद कल्पना सैनी, विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, आदेश चौहान, ममता राकेश, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, मेयर किरण जेसल, अनीता जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, उपाध्यक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विनय रोहेला, दर्जा राज्यमंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि, शोभाराम प्रजापति, सुनील सैनी, श्यामवीर सैनी, जयपाल सिंह चौहान, देशराज कर्णवाल, श्री गंगा सभा अध्यक्ष नितिन गौतम, बीजेपी जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा, मधु सिंह, महामंत्री बीजेपी आशु चौधरी, व्यापार मण्डल प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव नेयर, महानगर व्यापार मण्डल अध्यक्ष सुनील सेठी, मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, मण्डलायुक्त विनय शंकर पाण्डे, सचिव डॉ.पंकज कुमार पाण्डे, धीराज सिंह गर्ब्याल, युगल किशोर पन्त, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि आद उपस्थित थे।

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबित परीक्षाएं जल्द कराए जाने, रुके हुए परीक्षा परिणाम अविलंब घोषित किए जाने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बीएएमएस छात्रों का अनिश्चितकालीन जारी है। छात्रों ने मांगों पर गौर नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

कैम्पस में धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही और उदासीनता बरतने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि विवि का शैक्षणिक कैलेंडर पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। साल 2019 से 2022 तक के बैच के छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय गेट पर एकत्रित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में डटे रहे। छात्रों ने विवि प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे के भीतर कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। छात्रों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि ना तो उनकी परीक्षाएं समय पर आयोजित की जा रही है और ना ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहे हैं। इससे ना सिर्फ उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है, बल्कि विवि में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी का कोर्स करने वाले छात्रों का करियर भी दांव पर लग गया है।

अनिश्चितकालीन धरना दे रहे छात्रों का कहना है कि अब यह विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ आर पार की लड़ाई हो गई है। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई वरिष्ठ अधिकारी छात्रों से बातचीत के लिए नहीं पहुंचा, इससे छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। गौरतलब है कि छात्र 2019-20 और 2021 बैच के परीक्षा परिणामों की घोषणा नहीं होने, 2018 बैच की डिग्री जारी करने में हो रहे विलंब की वजह से आंदोलन के राह पर हैं। धरना दे रहे छात्रों का आरोप है कि इन तमाम बिंदुओं पर कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखा गया उसके बावजूद मांगों की अनदेखी की जा रही है। डिग्री नहीं मिलने की वजह से आगे की पढ़ाई व रोजगार के अवसरों के लिए वह आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक संदीप शर्मा ने इंडिया प्रिन्टर शॉप न. 06 संगम प्लाजा धर्मपुर देहरादून से मुद्रित करवाकर मोहक्कमपुर खुर्द पोस्ट आई.आई.पी. रेलवे क्रसिंग हरिद्वार रोड़ देहरादून (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।

प्रधान सम्पादक : संजीव शर्मा

संपादक: संदीप शर्मा

सह सम्पादक : डा. विष्णु बिश्वास

संजीव अग्निहोत्री गढ़वाल प्रभारी

अल्मोड़ा जिला प्रभारी : रोहित कार्की

अल्मोड़ा संवाददाता : रक्षित कार्की

ब्यूरो चीफ : राजीव अग्रवाल

Email.
indiawarta@gmail.com
indiawarta@rediffmail.com
Web Site
www.indiawarta.com
R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104
M- 7500471414,7500581414

नोट- समाचार पत्र में सभी पद अवैतानिक हैं।
किसी भी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा।
R.N.I NO. UTTHIN/2011/39104

दिव्यांग मतदाताओं के बूथों को चिन्हित कर जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएँ : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

– समाज कल्याण विभाग हर तीन माह में नए दिव्यांग मतदाताओं की सूची कराए उपलब्ध– सीईओ
– मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली सुगम मतदान हेतु राज्य स्तरीय प्रचालन समिति की बैठक

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में सुगम मतदान हेतु राज्य स्तरीय प्रचालन समिति "स्टेट स्टेयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन" की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्यों आयुक्त, नि:शक्त जन, निदेशक समाज कल्याण, निदेशक शिक्षा, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग,महानिदेशक सूचना एवं विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधियों से विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों पर आयोग द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम सभी सुविधाओं एश्योर मिनिमम फैसेलिटी (एएमएफ) को सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएं। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि विभाग में दर्ज दिव्यांग पेंशनधारकों को मतदाता सूची में शत प्रतिशत पीडब्ल्यूडी श्रेणी में शामिल कराने के दृष्टिगत 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1जुलाई और 1 अक्टूबर की अर्हता तिथि के आधार पर हर तीन माह में अपडेटेड सूची निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसएसआर) में इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी मतदाताओं का चिन्हिकरण कर उनके पोलिंग बूथ के अनुसार उन्हें एएमएफ सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक स्वीप पीडब्ल्यूडी आईकॉन चिन्हित किए जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एनआईईपीवीडी को ब्रेल आधारित मतदाता जागरुकता सम्बंधी प्रचार सामग्री तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने ऽस्टेट स्टेयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शनऽ के सम्बंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार वर्ष-2018 से राज्य में कुल 03 प्रकार की समीतियां गठित हैं जिनमें राज्य,जनपद एवं विधान सभा स्तर पर समय-समय पर बैठक आयोजित की जाती हैं। प्रस्तुतीकरण में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में 30-39 आयु वर्ग के दिव्यांग जनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि आयोग का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों द्वारा पोलिंग बूथों पर दी जाने वाली न्यूनतम सुविधा जैसे - रैम्प, व्हील चेयर, सुविधानुसार शौचालय, पीने का पानी, शेड, बैठने की सुविधा आदि के आभाव को दूर करना है।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री किशन सिंह नेगी,सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास अपर जिलाधिकारी, देहरादून श्री जय भारत सिंह, संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा डा एएस उनियाल,संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण श्री गीता राम नौटियाल,उप निदेशक, सूचना श्री रवि बिजारनियां,संयुक्त निदेशक, लेपोरेसी, श्री जितेन्द्र नेगी सहित माध्यमिक शिक्षा, लोक निर्माण विभाग एन0आई0ई0पी0वी0डी, सर्व कल्याण विकास समिति, दिव्य एजुकेशनल सोसाईटी, नन्ही दुनिया, अरूणिमा फाउन्डेशन, चशायर होम, बाल वनिता आश्रम के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने की प्रदेश के भीतर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा

इंडिया वार्ता ब्यूरो

देहरादून । मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय स्थित अपने सभागार में प्रदेश के भीतर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश के अंतर्गत एनएच पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की सड़कों की स्थिति और प्रगति की विस्तार से जानकारी ली।

मुख्य सचिव ने एनएच पीडब्ल्यूडी की सड़कों की बॉटल नेक की जानकारी लेते हुए उन्हें दुरुस्त किए जाने के लिए शीघ्र योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने वन एवं वन्यजीव संस्तुतियों के लिए लगातार केन्द्र एवं राज्य स्तरीय सम्बन्धित विभागों से अनुवर्तन करते रहने की बात भी कही। कहा कि एनएच पीडब्ल्यूडी द्वारा लम्बित मामलों में सम्बन्धित जिलाधिकारियों और फारेस्ट के साथ लगातार बैठकें आयोजित करते हुए लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।

मुख्य सचिव ने ऋषिकेश बाईपास में बायपास को ऋषिकेश से शिवपुरी तक बढ़ाए जाने हेतु कार्यवाही शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र के स्तर से प्राप्त होने वाली स्वीकृतियों के लिए लगातार प्रयास किए जाएँ। उन्होंने कलियासौड़ रिअलाइनमेंट और जोशीमठ बाईपास रिअलाइनमेंट कार्य पूर्ण किए जाने के लिए टाईमलाइन निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाने के लिए लगातार उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कार्यों को समय से पूरा किए जाने के लिए जिन कार्यों को समानान्तर शुरू किया जा सकता है, उन्हें शुरू कर लिया जाए।

मुख्य सचिव ने एनएचएआई के अंतर्गत बन रही सड़कों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने एनएचएआई के बल्लुपुर पोंवटा साहिब पैकेज 1 और 2, झाझरा-आशारोड़ी 4 लेन, हरिद्वार बायपास सहित विभिन्न स्तरों पर चल रहे प्रोजेक्टों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कार्यों को निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाएं।

सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 3589.99 किमी है, जो एनएच पीडब्ल्यूडी के पास 2028.19 किमी, बीआरओ के पास 986.8 किमी, एनएचआईडीसीएल के पास 130 किमी और एनएचएआई के पास 445 किमी है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग के कुल 53 कार्य होने हैं, जिनमें से 47 को स्वीकृति प्राप्त है। 42 कार्य अवार्ड किए जा चुके हैं, जिनमें से 30 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 12 कार्यों पर कार्य गतिमान है। 5 कार्य अवार्ड होने बाकी हैं और 6 कार्य स्वीकृत होने बाकी हैं। इस अवसर पर अपर सचिव विनीत कुमार एवं रीजनल ऑफिसर एनएचएआई विशाल गुप्ता एवं पीडी एनएचएआई पंकज भी उपस्थित थे।

पाठको के लिए

मान्यवर पाठकगण

१. दैनिक इंडिया वार्ता समाचार पत्र हेतु अपने व्यक्तिगत या संस्थान की ओर से प्रकाशनार्थ लेख/समस्याएं व समाचार हमें भेजे व प्रति दिन नियमित रूप से समाचार पत्र प्राप्त करने को कार्यालय से सम्पर्क करे।

२. समाचार पत्र के बारे में आप के विचार व सुझाव आमंत्रित है।

३. नियमित पाठक बनने के लिए आपके द्वारा समाचार पत्र की सदस्यता ग्रहण करना प्रार्थनीय है।

४. व्यक्तिगत एवं व्यापारिक संस्थानो के तथा अन्य विज्ञापन आमंत्रित है।

सम्पादक
दैनिक इंडिया वार्ता
कार्यालय : मोहकमपुर खुर्द नियर आई आई पी हरिद्वार रोड देहरादून।
दूरभाष: 7500581414,9359555222

उत्तराखंड : अनामिका शर्मा प्रकरण में गहरे सवाल, कांग्रेस ने की उच्च-स्तरीय SIT जांच की मांग

देहरादून,इंडिया वार्ता ब्यूरो। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाले अनामिका शर्मा प्रकरण में नए खुलासे और अनसुलझे सवालों का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इस पूरे मामले को सत्ता, संगठन और समाज के नैतिक पतन का खुला दस्तावेज बताते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की है। हरिद्वार जेल से बरामद एक मोबाइल फोन से कथित तौर पर सामने आए तथ्यों ने प्रदेश की राजनीति में तूफान ला दिया है।

दसौनी ने सवाल उठाया कि मात्र 10 वर्षों में अनामिका शर्मा को संगठन में इतने ऊंचे पद तक पहुंचाने के पीछे कौन लोग थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में समर्पित कार्यकर्ताओं की जगह संपर्कों और समीकरणों ने ले ली है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अनामिका शर्मा का यह बयान कि "यदि मैंने मुंह खोला तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे" ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है।

गरिमा मेहरा दसौनी ने इस प्रकरण की हाईकोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच, मोबाइल डेटा की फोरेंसिक जांच और संबंधित नेताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया, तो कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। यह मामला अब केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति के गिरते मूल्यों और नैतिकता पर गहरा प्रश्नचिह्न लगा रहा है, खासकर एक मां द्वारा अपनी नाबालिग बच्ची से देह व्यापार कराने के कथित आरोपों ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है।